Shodh Sari-An International Multidisciplinary Journal

@2024 International Council for Education Research and Training
2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
ISSN: 2959-1376
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

ग्रामीण विकास के लिए चुनौतियां और अवसर: बिलासपुर जिले का प्रतीकात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़)

कुमार, प्रवीण[1], व सेठ, मनीष [2]

रिसर्च स्कॉलर[1], सहायक प्राध्यापक[2]

वाणिज्य विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छतीसगढ़

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सार

भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। इसकी आत्मा गाँवों में निवास करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से ग्रामीण और कृषि है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए गांवों का उत्थान आवश्यक है। समृद्ध मानव संसाधन वाले इस देश की ल70 प्रतिशत आबादी लगभग 6 लाख गांवों में रहती है। इस विशाल विविधता वाले देश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण, बीमारी जैसी कई समस्याएं देखी जा सकती हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया था। राष्ट्र पिता ने पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास की परिकल्पना की थी। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन विधेयक ग्रामीण विकास के मामले में एक मील का पत्थर साबित हुआ। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाएं ग्रामीण प्रगति और पुनर्गठन के लिए प्रभावी साबित हुई बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया, रायपुर, कोरबा, और जांजगीर, जिलों से घिरा हुआ है। बिलासपुर जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 3508.48 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में पहाड़ी तथा दक्षिण में समतल है। इस जिले में औसत वर्षा लगभग 1220 मिमी है। यह जिला आगर, मनियारी और अरपा नदियों से घिरा हुआ है। बिलासपुर जिले की कुल जनसंख्या लगभग 12663629 है जिसमें से 79% लोग गांवों में रहते हैं और कुल जनसंख्या घनत्व लगभग 674 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस जिले के ग्रामीण हिस्सों

@2024 International Council for Education Research and Training 2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
ISSN: 2959-1376 DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति दयनीय है। ग्रामीण विकास के मार्ग में कई बाधाएं हैं, जिनके व्यवस्थित समाधान की आवश्यकता है। इस जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिस पर सरकार और योजनाकारों का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भौतिक और मानव संसाधनों के उचित विकास से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है ताकि प्रगति का खाका तैयार किया जा सके।

मुख्य शब्दः वृहत्तम, लोकतांत्रिक, विपुल, पुर्नसंरचना, बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़, ग्रामीण विकास ।

<u>भूमिका:</u>

भारत, एक विकासशील देश है, जहाँ लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की परेशानियों में जीवन-बसर करती है, जहाँ उनके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है। विकास में सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति शामिल हैं। ग्रामीण विकास एक अनिवार्य आवश्यकता है। गाँवों की वृद्धि के बिना समाज और देश दोनों अभी विकसित नहीं हुए हैं। पंचायतीराज व्यवस्था ने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने ग्रामीण विकास की कल्पना नहीं की थी।

रामराज्य से प्रेरित ग्राम स्वराज था। राष्ट्र निर्माताओं नेहरू और अम्बेडकर ने एक विकेन्द्रित शासन व्यवस्था पर बल दिया था। पंचायतीराज की बुनियादी बातें हैं: प्रशासन और सत्ता का विकेंद्रीकरण, जनता को नीति बनाने में शामिल करना और एक वर्ग विहीन समता मूलक समाज का निर्माण। वास्तव में, पंचायतीराज व्यवस्था लोकतंत्र का आधार है।

पंचायतीराज के माध्यम से राष्ट्रीय विकास का तंत्र उर्जा और स्फूर्त्ति से भर सकता है, जो विकेन्द्रीकरण का प्रभावी साधन है। ग्रामीण विकास का उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन-स्तर में सुधार, उनकी आय में वृद्धि, आर्थिक-सामाजिक सम्पन्नता, समानता, एकता और विषमता को दूर करना है।

इसमें अर्थतंत्र के समन्वय के साथ-साथ काल और क्षेत्र के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी और पर्यावरण का विकास भी शामिल है, जो ग्राम निवास प्रत्यावर्तन में शामिल हैं। ग्रामीण विकास प्रक्रिया समन्वय पर आधारित है, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्राम्य जनसंख्या को उच्च जीवन-स्तर प्राप्त करने के साथ-साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

प्रदान करना है।ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, योजनाकारों, प्रशासकों, राजनेताओं और भूगोल वेत्ताओं के लिए एक दिलचस्प विषय रहा है।

गाँधीजी ने गाँव को देश का विकास का हिस्सा समझा। ग्रामीण विकास का असली चित्र गाँव से प्राप्त होगा जब विकास का कार्य गाँव से शुरू होगा। पंडित नेहरू ने मान लिया कि भारत गरीब है क्योंकि उसके कई गाँव गरीब और बेहाल हैं। गाँवों को आर्थिक विकास मिलेगा तो देश सुदृढ़ और संपन्न होगा। ग्रामीण विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन और कार्यान्वयन पंचायतीराज के माध्यम से हुआ है, जिससे ग्रामीण विकास की सेहत प्रभावित हुई है।

उद्देश्य:

वर्तमान लेख का उद्देश्य निम्नलिखित है:

- ग्रामीण विकास की नवीनतम प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना।
- ग्रामीण विकास में उत्पन्न समस्याओं का पता लगाना
- ग्रामीण विकास की समस्याओं को हल करने के लिए अपेक्षित उपायों का प्रस्ताव करना।
- ग्रामीण विकास और संभावनाओं का पता लगाना

साहित्य समीक्षा:

भौगोलिक साहित्य में ग्रामीण विकास का अध्ययन एक विषय है। इस दिशा में कई राज्यस्तरीय प्रयास हुए हैं, लेकिन बिलासपुर जिले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत में शिवलकर की पुस्तक 'ग्रामीण विकास की व्यथा और कथा' में ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रयासों का उल्लेख किया गया है। जवाहर लाल नेहरू की पुस्तक "सामुदायिक विकास और पंचायतीराज की भूमिका" में सिद्धांत और उपयोग की व्याख्या की गई है। "समन्वित विकास संकल्पना: उपागम एवं मूल्यांकन" में प्रमोद सिंह ने समन्वित विकास का उपयोग करने पर जोर दिया है।

बेचन दुबे ने समन्वित ग्रामीण विकास के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आर. सी. अरोरा ने "समन्वित ग्रामीण विकास" में ग्रामीण विकास के

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

कई आयामों को समझाया है। गोपाल प्रसाद साह ने अपने शोध-प्रबन्ध, "भागलपुर जिले के सबौर प्रखण्ड का एक अध्ययन" में सबौर के ग्रामीण विकास की समस्याओं और संभावनाओं को समझने की कोशिश की है। अपने शोध-प्रबन्ध में प्रशांत कुमार ने ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों, समस्याओं और निराकरणों की चर्चा की है।

अध्ययन का क्षेत्र

बिलासपुर शहर लगभग 400 वर्ष पुराना है और “बिलासपुर” का नाम “बिलासा” नामक महिला के नाम पर रखा गया है। कई प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, बिलासपुर ने बहुत कुछ विकसित किया है। बिलासपुर जिला 21.47° से 23.8° उत्तर अक्षांश और 81.14° से 83.15° पूर्व देशान्तर के बीच स्थित है।बिलासपुर जिला उत्तर में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला, पश्चिम में मुंगेली और कबीरधाम जिला, दक्षिण में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला और पूर्व में कोरबा और जांजगीर-चांपा जिला से घिरा हुआ है।

जिले का क्षेत्रफल लगभग 3508.48 वर्ग किलोमीटर है। जिले की कुल जनसंख्या लगभग 2663629 जिसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 13,51,574 और 1312055 है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 70.78 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता लगभग 81.54 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता लगभग 59.71 प्रतिशत है, जबकि लिंगानुपात लगभग 970 प्रति हजार है एवं जनसंख्या घनत्व लगभग 674 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बिलासपुर जिले में 11 तहसील, 4 ब्लॉक और 708 गांव शामिल हैं। रायपुर-भिलाई-दुर्ग ट्राई-सिटी मेट्रो क्षेत्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा शहर है।

छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय, बिलासपुर के गांव बोदरी में स्थित है। जिला बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी के नाम से भी जाना जाता है। बिलासपुर उच्च न्यायालय एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। बिलासपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है

अध्ययन क्षेत्र की अवस्थिति

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

Source: https://bilaspur.gov.in

<u>आँकड़े के स्रोत और विधि:</u> प्रस्तुत लेख कार्य के लिए आंकड़े प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से संग्रहित किए गए हैं और निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया गया है:

<u>प्राथमिक स्रोत:</u>

इस स्रोत से क्षेत्रीय अध्ययन के लिए बिलासपुर जिले के पांच गाँवों बाशा ,बहतरई, बिरकोना,

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

चिलहाटी, भरारी. का यादृच्छिक रूप से प्रतिचयन किया गया हे:

द्वितीयक स्रोत: इसमें जनगणना पुस्तिका, सांख्यिकी पुस्तिका और अप्रकाशित साहित्यिक प्रबन्ध, लेख, इंटरनेट, पत्रिका आदि से जानकारी मिली है।

प्रतिदर्श हेतु चयनित ग्रामों में विकास योजनाओं से परिचय और लाभान्वितो की विवेचना,

क्र.सं.	योजना	अवगत		लाभान्वित	
		हाँ %	नहीं %	हाँ %	नहीं %
1.	इंदिरा आवास	56	44	33.67	66.33
2.	मनरेगा	65	35	40.64	59.36
3.	उज्ज्वला	90	10	65.15	34.85
4.	वृध्दा पेंशन	54	46	86.00	14.00
5.	अन्त्योदय	88	12	82.38	17.62
6.	जननी योजना	43	57	57.37	42.63
7.	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क	100	-	73.27	26.73
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य	78	22	59.38	40.62

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण एव परिकलित आकड़ा

व्यक्तिगत सर्वेक्षण से पता चला कि इंदिरा आवास योजना से सभी उत्तरदाता अवगत हैं, 33.67% लाभान्वित हैं और 66.33% लाभ से वंचित हैं। शत प्रतिशत उत्तरदाता मनरेगा योजना की जानकारी रखते हैं, जिसमे 40.64 % से 59.36 % उत्तरदाता इस योजना का लाभ उठाते हैं, जबकि उत्तरदाता इस योजना का लाभ उठाते हैं। उत्तरदाता को लाभ नहीं हुआ है। 90% उत्तरदाताओं को उज्ज्वला योजना की जानकारी है, 10% इस योजना से अनजान हैं, जिसमें 65.15% उत्तरदाताओं को लाभ मिलता है और 34.85% उत्तरदाताओं को लाभ नहीं मिलता है।

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

वृद्धा पेंशन योजना से 100% उत्तरदाता अवगत हैं, 86% लाभान्वित हैं और 14% लाभान्वित नहीं हैं। 100% उत्तरदाताओं को अंत्योदय याेजना की जानकारी है, जिसमें 82.38%, % और 17.62%, लाभान्वित हैं और लाभान्वित नहीं हैं। मुख्य रूप से महिलाओं के लिए संचालित जननी सुरक्षा योजना से 43 % 57% और 57.37 % 42.63% उत्तरदाता क्रमशः अवगत हैं और अवगत नहीं हैं; मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी 100% उत्तरदाताओं के पास है, जिसमें 73.27% उत्तरदाता लाभ ले रहे हैं और 26.73% उत्तरदाता लाभ नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था से 78% उत्तरदाता अवगत हैं, 22% अवगत नहीं हैं, 59.38 प्रतिशत उत्तरदाता लाभार्थी हैं, और 40.62% उत्तरदाता लाभ से वंचित हैं।

समस्याएं

वर्तमान लेख का अध्ययन क्षेत्र बिलासपुर जिला है, जहाँ ग्रामीण विकास के रास्ते में कई बाधाएँ हैं,

- **पक्की सड़कों का पूर्ण निर्माण नहीं होना**

सड़कों का निर्माण, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचने देता है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।बिलासपुर जिले के अधिकांश गाँवो में सड़कों का पूरा विकास नहीं हुआ है, जिससे किसान खेतों से फसलों को आसानी से बाजार में बेच नहीं पाते हैं।

- **कृषक ऋण**

कृषि के पिछड़ेपन का कारण ऋणग्रस्तता है। आज ग्रामीण विकास में ऋणग्रस्तता एक प्रमुख बाधा रही है। कृषक परिवार कृषि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए ग्रामीण साहूकारों और बैंकों से ऋण लेकर काम करते हैं, लेकिन मानसून की अनिश्चितता, कम गुणवत्ता वाले बीज, पर्यावरणीय हानि आदि कारणों से वांछित उत्पादन नहीं मिल पाता है। नतीजतन, लागत पूँजी भी नहीं निकलती, जिससे कृषक ऋण के दुष्चक्र में फँसते जाते हैं।

- **नियमित आमसभा नहीं होना:**

ग्राम पंचायत के मुखिया नियमित रूप से आमसभा नहीं बुलाते हैं। प्रशासन के

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

सहयोग से, जनप्रतिनिधि नियमित रूप से आमसभा की बैठक करते हैं। जन प्रतिनिधियों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय के कारण गाँवों में कुछ लोग अधिक लाभ उठाते हैं और कुछ लोग इससे वंचित रहते हैं।

- **कृषि उद्योगों का अभाव और पलायन**

  औद्योगिक साधनों की उपलब्धता अध्ययन क्षेत्र बिलासपुर जिले में बहुत कम है। यहाँ के मुख्य संसाधनों में कृषि उत्पादन महत्वपूर्ण है। आज भी कृषि आधारित उद्योगों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ है, इसलिए युवा ग्रामीण बेरोजगार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आदि राज्यों में हर साल पलायन करते रहते हैं।

- **शौचालय की कमी**

  अध्ययन क्षेत्र में हर ग्रामीण घर में शौचालय नहीं है, इसलिए लोग यत्र-तत्र मलमूत्र त्यागते हैं। नतीजतन, गंदगी फैल जाती है और कई रोगी फैलने की आशंका बढ़ जाती है।

- **अशिक्षा**

  शिक्षा ग्रामीण विकास का हिस्सा है और अशिक्षा साक्षरता दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। 21वीं सदी में अधिकांश ग्रामीण लोग सिर्फ अपना हस्ताक्षर करना जानते थे, लेकिन आज भी वे अखबार या चिट्ठी-पत्री नहीं पढ़ पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित नहीं हो पाते हैं।

- **स्वच्छ जल का अभाव**

  वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की कमी है, जो ग्रामीण लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है, इसलिए वे गंदे जल का उपयोग करते हैं। इससे कई प्रकार के संक्रमण एवं बीमारी होने की संभावना बनी रहती है।

- **स्थानीय आवास समस्या**

  वर्तमान समय में गाँवो गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो अपने लिए घर बनाने में असमर्थ हैं। केन्द्र सरकार ने बिलासपुर जिले में इंन्दिरा आवास योजना लागू की है, जिससे ग्रामीण आवास की समस्या कुछ हद तक दूर हो गई है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम सफल हैं

समाधान के तरीके

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

बिलासपुर जिले में ग्रामीण विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जरूरत है:

- **ग्रामीण सड़कों को पूरी तरह से पक्की किया जाए**

गाँवों के विकास में सड़कों का पूरा पक्कीकरण महत्वपूर्ण है। जब तक गाँव की सड़क पूरी तरह से पक्की नहीं हो जाएगी, ग्रामीण अपनी सभी समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे।

- **स्वच्छ जल का पहुँच हो**

मुख्यमंत्री ने अध्ययन क्षेत्र में सात निश्चित योजनाओं के माध्यम से हर घर में नल जल या नलकूप लगाया है, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके और बीमारियां कम हों।

- **कृषि आधारित कंपनियां बनाएँ**

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, गरीबी और आय और धन का समान वितरण सबसे बड़ी समस्याएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से जिले में नवीन रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आय में वृद्धि होगी और कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- **सुविधाजनक शौचालय का निर्माण**

गाँवों में शौचालय की कमी से लोग खुली जगह पर शौच करते हैं, जिससे गंदगी फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए प्रत्येक घर में और सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ शौचालय बनाने की जरूरत है। इससे बहुत सी संक्रमणशील बीमारियाँ दूर हो जाएंगी।

- **आमसभा की नियमित बैठक पंचायत भवन में**

ग्राम पंचायत में आमसभाओं के माध्यम से बुजुर्गों द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक मुद्दे उठाए जाना चाहिए। आमसभा की नियमित बैठक भी होनी चाहिए।

- **निष्पक्ष निर्णय प्रणाली**

गाँव के जनप्रतिनिधि कुछ लोगों को निर्णय देते हैं और कुछ नहीं। यही कारण है कि जनप्रतिनिधि सभी लोगों को समान मानते हैं और कमजोर और वंचित लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को पक्षपातपूर्ण निर्णय का एहसास न हो। इससे समाज में सकारात्मक भावना पैदा होगी।

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

- **परिवार व्यवस्था अपनाएँ**

  बिलासपुर जिले में जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण लोगों को परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाना होगा। "हम दो हमारे दो " की नीति भी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना कई समस्याओं का समाधान होगा। स्कूली स्तर से जनसंख्या शिक्षण शुरू होना चाहिए।

- **वंचित लोगों के लिए आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करें**

  केंद्र सरकार की इंदिरा आवास योजना अध्ययन क्षेत्र में लागू हो रही है। यह योजना गरीब लोगों को घर देती है। इसलिए, ताकि बिलासपुर जिले की आवास संबंधी समस्या दूर हो सके, इस योजना का लाभ अधिकांश गरीब लोगों को मिलना चाहिए।

- **वित्त और साख की व्यवस्था**

  कृषक उत्पादन को बढ़ाना तभी संभव है जब उनके पास पर्याप्त धन है। बांका जिले में कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए नवीन तकनीक का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और किसानों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाएँ। इसके लिए गांव में सहकारी संस्थाएं और बैंकों का विस्तार होना चाहिए।

- **शिक्षा का प्रचार**

  ग्रामीण लोग आज भी चिट्ठी-पत्री और अखबार पढ़ नहीं पाते, जो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। इसलिए अनपढ़ लोगों को भी शिक्षित करने के लिए सरकार को चुना जाना चाहिए और व्यापक रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। नतीजतन, ग्रामीण सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी रख सकेंगे और उनसे लाभ उठाने के लिए प्रयास कर सकेंगे।

सम्भावना

छत्तीसगढ़ राज्य में पहाड़, पठार और समतल क्षेत्र हैं। जिले के उत्तरी भाग में अरपा नदियों से खेती होती है। इस खंड में धान उत्पादन की कृषि में बहुत सारे अवसर हैं। अध्ययन क्षेत्र में 16.45 स्थायी परती जमीन उपलब्ध है, जहाँ कृषि में वृद्धि करने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक कृषि उपकरण, उन्नत बीज, सिंचाई और उर्वरक आदि की व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ बिलासपुर

@2024 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2024, Vol. 03, Issue 03, 49-59
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7717

खुटाघाट बाँध, स्थित हैं, जहाँ आप मत्स्य पालन कर सकते हैं साथ ही खुटाघाट प्रखंड में पर्वत और रतनपुर , की सीमा पर झरना पहाड़ भी हैं. जिले में, रतनपुर माहामाया शक्तिपीठ हैं, जहाँ पर्यटन करने की बहुत सी जगहें हैं। जिले का दक्षिणी हिस्सा बंजर है, जहाँ वन उत्पादन से रेशम उद्योग की प्रचुर संभावनाएँ हैं। बायोडीजल और एथेनाल बनाने के लिए बंजर भूमि पर केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

बिलासपुर जिला कृषि प्रधान और ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इसलिए यह एक विकासशील क्षेत्र है जहाँ ग्रामीण विकास ही सामाजिक-आर्थिक प्रगति को प्रेरित कर सकता है। विपन्न और सुविधा विहीन गाँवों में सुधार की कल्पना नहीं हो सकती। यह सिर्फ एक जिला है, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के एक पिछड़े क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है जहाँ विकास और समृद्धि का प्रकाश फैलाने की जरूरत है। यहाँ समुचित शोषण-दोहन के माध्यम से प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को बढ़ावा देकर आदर्श ग्रामीण भारत का निर्माण किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

- https://bilaspur.gov.in
- जवाहर लाल नेहरू, की पुस्तक "सामुदायिक विकास और पंचायतीराज की भूमिका"
- आर. सी. अरोरा, ने "समन्वित ग्रामीण विकास"
- गोपाल प्रसाद साह, ने अपने शोध-प्रबन्ध, "भागलपुर जिले के सबौर प्रखण्ड का एक अध्ययन"
- प्रमोद सिंह, "समन्वित विकास संकल्पना: उपागम एवं मूल्यांकन"
- प्रशांत कुमार "ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों, समस्याओं और निराकरणों की चर्चा"

Received on April 22, 2024

Accepted on May 26, 2024

Published on Jul 01, 2024

ग्रामीण विकास के लिए चुनौतियां और अवसर: बिलासपुर जिले का प्रतीकात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़) © 2024 by प्रवीण कुमार व मनीष सेठ is licensed under CC BY-NC-ND 4.0